भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3557
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नैदानिक परीक्षण

3557. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एमआरआई, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी जैसे प्रमुख नैदानिक परीक्षण और अन्य उच्च लागत वाले परीक्षण आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत तब तक शामिल नहीं हैं जब तक कि रोगी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है;
(ख) यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण नैदानिक सेवाओं को बाहर रखने के क्या कारण हैं, जो जान को खतरे वाली कई स्थितियों का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं;
(ग) क्या सरकार के पास इन नैदानिक परीक्षणों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के दायरे का विस्तार करने की कोई योजना है, जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर वित्तीय बोझ कम हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार के पास इन सेवाओं को शामिल करने की कोई योजना है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थी को सस्ती दरों पर ये नैदानिक परीक्षण उपलब्ध हों, लागू किए जा रहे वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) 1961 प्रक्रियाओं के लिए 27 विभिन्न चिकित्सा विशिष्टताओं में अंतरंग रोगी सेवाओं से संबंधित मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत उपचार पैकेज बहुत व्यापक तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और इसमें उन सभी संकेतक परीक्षणों की लागत शामिल है जो रोगी के निदान और उपचार के हिस्से के रूप में आवश्यक हो सकते हैं। रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स (सीटी स्कैन, एमआरआई, न्यूक्लियर इमेजिंग सहित इमेजिंग) जैसी कुछ महंगी उच्च-स्तरीय जाँचें योजना के तहत किसी भी चिकित्सा पैकेज में ऐड-ऑन पैकेज के रूप में बुक की जा सकती हैं।

(ग) और (घ): योजना में समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियमित अद्यतनीकरण जैसे नई प्रक्रियाओं को शामिल करना, नए अस्पतालों को सूचीबद्ध करना, नए लाभार्थियों को शामिल करना तथा अन्य सुधार किए जाते हैं।

*****